



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1999/चैत्र 11, 1921

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1999/CHAITRA 11, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1999

विषय : एन बी आर के आयातों में संबंधित पाटनरोधी सीमा-शुल्क को समीक्षा—अंतिम निष्कर्ष ।

सं. 38/6/97-एडीडी.—में यथासंगोष्ठि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके सीमा शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 का पालन करते हुए :—

क. पद्धति

1. जांच के लिए नीचे दी गई पद्धति का पालन किया गया है :—

- (i) पदनामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने अधिसूचना, तारीख 19-10-1995 द्वारा जापान मूल के या वहां से नियांति एन बी आर पर पाटनरोधी सीमा-शुल्क की समीक्षा का आरंभ करते हुए अधिसूचना सं. 38/4/97/एडीडी, तारीख 12 मई, 1995 जारी की।
- (ii) अधिग्रन्थना, तारीख 19-10-1995 द्वारा प्राधिकारी ने जांच समाप्त की थी जिसे इस अधिसूचना में “पिछली जांच” कहा गया है।
- (iii) अधिकारी ने जापान (जिसे इसमें इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) मूल के या वहां से नियांति, कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 4002.59 के अंतर्गत वर्गीकृत एन बी आर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी सीमा-शुल्क की समीक्षा करते हुए एक सार्वजनिक सूचना तारीख 12 मई, 1995 को भारत के राजपत्र, असाधारण में जारी की।
- (iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात नियांतकों और उद्योग एसोसिएशंस (जिनके विवरण पिछली जांच के दौरान वाढ़ी, गुजरात अपार पॉलीमर्स लि. ने उपलब्ध कराए थे) को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार, अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया।
- (v) प्राधिकारी ने भारत में एन बी आर के सभी ज्ञात आयातकों एवं उपभोक्ताओं (जिनका विवरण पिछली जांच के दौरान गुजरात अपार पॉलीमर्स लि. द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को भेजी और उनमें पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए कहा।

vii) जौच की अवधि के दौरान भारत में एन बी आर के आयातों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एंड कस्टम्स [सी बी ई सी] से अनुरोध किया था ।

VIII) नियम 6(2) के अनुसार जापान के नई दिस्ती स्थित राजदूतावास को समीक्षा जौच के आरंभ की सूचना दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों / उत्पादकों से प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देने के लिए अनुरोध करें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति तथा ज्ञात निर्यातकों / उत्पादकों की सूची, राजदूतावास को भी दी गई थी । तथापि, किसी भी निर्यातक / उत्पादक ने काई उत्तर नहीं दिया है ।

IX) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में एन बी आर के ज्ञात आयातकों और / या उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई ।

X) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली की एक प्रति गुजरात अपार पॉलीमर्स लिं, [जिसे इसमें इसके बाद गुजरात अपार भी कहा गया है] को अर्जित नहीं थी । गुजरात अपार ने अपना उत्तर भेजा है ।

XI) प्राधिकारी ने गतिक रूप से विचार सुनने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई नवम्बर, 1998 को आयोजित की । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से, उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया गया था । पार्टियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों की प्रतियां ले लें और उनके उत्तर दें ।

XII) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर दर्शीएक फाइल, किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा देखने के लिए खुली रखी थी ।

XIII) जौच 1.4.97 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए की गई थी ।

XIV) पूर्ववर्ती नियमों के नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए आवश्यक समझे गए तथ्यों / आधारों की जाकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को दी गई थी और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इन निष्कर्षों में उपस्थितः विचार किया गया है ।

ख. गुजरात अपार के विचार

२. गुजरात अपार ने निम्नलिखित अभियेदन किए हैं :-

क) यद्यपि जापान और अन्यदेशों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क से गुजरात अपार को अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिली है, फिर भी कम्पनी को घोर अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्द्ध का सामना करना पड़ा है। सीमा शुल्कों का वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं है तथा पाटन मूल्यों पर आयात जारी है।

ख) जापान के निर्यातकों ने पाटन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। जापान में एन बी आर/सामान्य मूल्य, जापान कैमिकल बीक में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर तथ किया जा सकता है जिसके अनुसार यह येन 440 प्रति कि.ग्रा.]^{औसत का} है। औसत विनियम दर के अनुसार, सामान्य मूल्य अमरीकी दर से 3562 प्रति ग्रीटिंग टन बगता है।

ग) निर्यात मूल्य को, डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित सूचना के आधार पर निर्णियत नहीं किया जा सकता क्योंकि आयातक, अलग एच एस कोइस के माध्यम से एन बी आर की विलयरिंग कर रहे हैं। निर्यात मूल्य, विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर तथ किया जाना चाहिए जो जापान से रु0 61.28/ कि.ग्रा. के औसत सी आई एफ मूल्य पर 887 एन बी आर का आयात बताता है।

घ) निर्यात मूल्य में, भारत को निर्यातों पर हुए खर्च को रागायोजित करने के बाद 200% से अधिक के भारी पाटन का जारी रहना बताता है।

इ.) पाटन-रोधी-सीगा-शुल्क को शामिल कर लैडिंग तंत्रज्ञान उचित लाभकारी मूल्य नहीं दे सकती। संचयकारी हानियाँ ज्ञाती हैं तथा कम्पनी अपनी स्थापना के साथ रो अब तक कोई लाभांश नहीं दे सकती है।

च) निर्यातों में भविष्य में क्षति करने की बड़ी संभावना है, जैसा कि सीमा-शुल्क लगाने से पहले आयातों से साबित होता है।

छ) भारत में एन बी आर का उचित बिक्री मूल्य ऐसा होना चाहिए जिसरो आर एंड डी, तकनीकी सेवाओं, पूँजी की लागत आदि निकल सके। क्षणता उपयोग, काल्पनिक तंत्रज्ञान की बजाय स्वदेशी उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए।

ज) परिवर्तनशील पाटन-रोधी सीमा-शुल्क, डालरों में लगाया जाना चाहिए।

झ) कोरिया से आयातों पर पाटन-रोधी सीमा-शुल्क एक उपयुक्त स्तर तक बढ़ाया जाए।

ग. आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

3. किसी भी नियांतक / उत्पादक ने अधिकारी को न तो उत्तर दिया और न कोई टिप्पणी दी । कुछ आयातकों तथा ऑल इण्डिया रबड़ इंडस्ट्रीज ने अपने विचार भेजे हैं जो इस प्रकार हैं :
- क) प्राधिकारी ने रु0 19,306/- प्रति मी.टन का निम्नतर सीमा-शुल्क लगाया क्योंकि क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन से कम था ।
- ख) वर्ष 1993-94 के दौरान अमरीकी डालर 1058 के एफ ओ बी मूल्य के आधार पर, स्वदेशी उद्योग के लिए उचित बिक्री मूल्य रु0 89483/- (जाँच अवधि के लिए) बनता है जिसमें पाटन-रोधी सीमा-शुल्क शामिल है, किन्तु सी बी डी शामिल नहीं है ।
- ग) पाटनरोधिता समझौते के अनुच्छेद 11.2 में कहा गया है, कि जाँच में यह देखा जाना चाहिए कि क्या सीमा-शुल्क हटा देने अथवा बदल देने, दोनों से जारी रहने की संभावना है या दोबारा होने की संभावना है । गुजरात अपार को हुई आर्थिक क्षति, पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाने के बाद समाप्त हो गई है और यह कम्पनी की 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है जहां पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख है कि एन बी आर पर पाटनरोधी सीमा-शुल्क लगा देने के कारण गुजरात अपार सुविधाजनक स्थिति में है । यह इस तथ्य का फल है कि पाटन-रोधी सीमा-शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप गुजरात अपार ने जाभ कमाया है । अतः यह जाँच करना आवश्यक है कि राजा-शाला का देने या बदल देने से क्षति फिर से हो सकती है या नहीं ।
- घ) जाँच अवधि : एन बी आर के आयात अमरीकी डालर 1695 के औसत मूल्य पर 85% भी. टन के थे ।

- इड.१ भारत औसत सीआईएफ मूल्य पर आधारित, समीक्षा अधिकारी के दोगने लैंडड मूल्य रु. 111683 प्रति मी.टन बनता है जिसमें समान सीमा शुल्क शामिल नहीं है। स्वदेशी मूल्य रु. 111683 प्रति मी.टन+5% से अधिक रहता। अतः गुजरात अपार ने लगभग रु. 112000 प्रति मीट्रिक टन पर माल बेचा होता। अप्रैल, 1997 के दोगने स्वदेशी मूल्य रु. 91000 प्रति मीट्रिक टन का था। फैक्टरी एतर मूल्य रु. 83500 प्रति मीट्रिक टन बनता है। यह मूल्य, पाटनरोधी सीमा शुल्क लगाए बिना जापान से आयातों के लैंडड मूल्य से काफी नीचे है। पाटनरोधी सीमाशुल्क हटा देने से गुजरात अपार को अपने एनबीआर के लिए और भी अधिक उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- इच.१ एनबीआर पर सीमाशुल्क 85 प्रतिशत १९९३-९४ से घटकर ३१.३० १९९८ को यथार्थता 45% कर दिया गया है। इसी अधिकारी में पक्कीनाईद्वारा पर सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत कर दिया गया जिसके अंतर्गत एनबीआर की लागत में लगातार गिरावट आई।
- इछ.१ गुजरात अपार को आर्थिक हानि दोबारा नहीं हो सकती क्योंकि यदि पाटनरोधी सीमाशुल्क हटा दिया जाता है तो कम्पनी एनबीआर की बिक्री, लैंडड मूल्य से ^{कमी} रही है। कम्पनी की, आयातों के लैंडड मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचने में असमर्थता का कारण जापान से आयातों का प्रतिफल नहीं है। यह बात गुजरात अपार द्वारा स्वीकार की गयी है कि उन्हें कोरिया से आयातों के कारण प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर माल बेचना पड़ा है।
- इज.१ जापान से एनबीआर के आयातों का हिस्सा 1995-96 के 66 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 17.5 प्रतिशत रह गया है।
- इझ.१ अन्य सभी देशों से सीआईएफ निर्यात मूल्य, जापान से निर्यात के मूल्य से ऊँचा है जबकि सच्चाई ये है कि जापान से सामान्य मानक ग्रेडस का आयात किया जाता है और अन्य देशों से विशेष ग्रेड्स का आयात किया जाता है। इसके बावजूद जापान से आयातों की लैंडड कीमत अन्य देशों की तुलना में (इस समय लागू पाटनरोधी सीमा शुल्क को देखते हुए) ऊँची है।

(अ) 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू कर दिये जाने के बाद से आयात और ऑपिक महंगे हो गए हैं। यह विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, 6·844 प्रतिशत बनता है। अतः आयात डीईसी के अन्तर्गत या जब अपेक्षित ग्रेड, स्थानीय ग्रोतों से उपलब्ध ग्रेडस के स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं, तब ही किए जा रहे हैं।

(ट) जापान से आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क निम्नलिखित को देखते हुए हठ दिया जाना चाहिए :-

॥1॥ आयात मूल्य में वृद्धि,
॥1॥ सीमाशुल्कों में घटौती,
॥11॥ विनिमय दरों में वृद्धि,

॥1V॥ आयातों के लौंड मूल्य में वृद्धि,

॥V॥ गुजरात अपार को क्षति नहीं,
॥VI॥ गुजरात अपार की उत्पादन लागत में घटौती।

उपरोक्त को 'देखते हुए जापान से आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क हठ दिया जाना चाहिए।

५. श्राविकारी दारा जाँच

५. गुजरात अपार, आयातकों, उपमोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टीयों द्वारा किए गए अभियेदनों की जाँच की गयी है, विचार किया गया है और जहाँ कल्प भी उचित समझा गया है, उन पर इसमें इसके बाद गर्दा है।

६. विचाराधीन उत्पाद, स्वदेशी उद्योग तथा समान वस्तुएँ

५. विचाराधीन उत्पाद, स्वदेशी उद्योग तथा समान वस्तुओं के संबंध में पहले अधिसूचित किये गए औतेम निष्कर्ष अपरिवर्तित रहेंगे।

पाटन

जापान से किसी भी निर्यातिक या उत्पादक ने अधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। भारत में एनवीआर के आयातकों या उपभोक्ताओं में से किसी ने भी पाटन के निश्चयन से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है। गुजरात अपार ने दावा किया है कि जापान से पाटन जारी है और यह भी दावा किया कि जापान में एनवीआर का सामान्य मूल्य, जापान कैमिकल वीक में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर तय किया जा सकता है। चौके अन्य किसी भी हितवद्ध पार्टी ने कोई सूचना नहीं दी है, अधिकारी, जापान में एनवीआर का सामान्य मूल्य, जापान कैमिकल वीक में प्रकाशित सूचना के आधार पर तय करना उत्तीर्ण समझता है। और भी, चौके किसी भी अन्य हितवद्ध पार्टी ने मूल्य समायोजनों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है, इने गुजरात अपार द्वारा दी गयी सूचना एवं पैछली जाँच में विचारित आएँगे के आधार पर अनुमत कर दिया गया है।

च- क्षति तथा कारणात्मक संबंध

10. यह तर्क कि पाटनरोधी सीमाशुल्क के वर्तमान स्तर पर चार्ज करने या पाटनरोधी सीमाशुल्क के वर्तमान स्तर पर बिना चार्ज किए आयातों के लैंडेड मूल्य से गुजरात अपार के बिक्री मूल्य नोचे हैं, इस बात को निश्चित करने के लिए सम्बद्ध नहीं हैं कि यांदे वर्तमान में चालू पाटनरोधी सीमा शुल्क हव्य दिया जाता है तो स्वदेशी उद्योग को क्षाति होगी या नहीं। यह निश्चित करने के लिए कि इस समय चालू सीमाशुल्क जारी रखे जाएं या नहीं, एक मात्र संबद्ध बात, पाटनमार्जन तथा वर्तमान पाटनरोधी सीमाशुल्क पर विचार किये बिना क्षाति की सीमा है। गुजरात अपार का वास्तविक बिक्री मूल्य अन्य अनेक कारकों का परिणाम है। अधिकारी ने उंचित बिक्री मूल्य तय किया है और यह पाया है कि जाँच अवांध के दौरान आयातों का लैंडेड मूल्य, यांदे वर्तमान में चालू पाटनरोधी सीमाशुल्क को नहीं लिया जाता है तो स्वदेशी उद्योग के उंचित बिक्री मूल्य से नोचे था। और भी, कम्पनी की निदेशकभण्डल की रिपोर्ट में केवल यह वक्तव्य कि कम्पनी, एनवीआर पर पाटनरोधी सीमा शुल्क लगाए जाने के कारण सुविधाजनक स्थिति में है, से यह अर्थ नहीं निकलता कि वर्तमान में लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को स्थांगत कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, यांदे पाटनरोधी सीमाशुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योग को स्थिति सुधरी है तो यह स्वदेशी उद्योग की इस मांग को पुनः स्थापित करती है कि इसे अनुचित व्यापारित पोटित आयातों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विगत में सुविधाजनक स्थिति का अर्थ यह नहीं है कि भौविष्य में भी स्थिति सुविधाजनक रहे। विशेष रूप से जबकि विगत की सुविधाजनक स्थिति, समीक्षागत उपायों के कारण हो सकती है। जापान के बाजार फिस्से में कमी के कारण भी सीमाशुल्क समाप्त नहीं किये जा सकते। कोरिया से आयातों के निम्नतर लैंडेड गूल्य के कारण स्वदेशी उद्योग को निम्नतर मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होने वाली बात तथा कोरिया से आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क को उचित रूप से बढ़ाने की स्वदेशी उद्योग की मांग के संबंध में, अधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच केवल जापान के विस्तर है। कोरिया गणराज्य से आयातों पर पाटनरोधी सीमाशुल्क को, यांदे इन झोतों से आयातों से स्वदेशी उद्योग को क्षति हो रही है और सीमाशुल्कों का स्तर उचित है तब भी बिना जाँच संबंधी प्रक्रिया पूरी लिए बिना बदला जाना समव्य नहीं है।

टृष्ण - अंतिम निष्कर्ष

11. उपरोक्त पर विचार करने के बाद अधिकारी का मत है कि :-

क. जापान मूल के या वहाँ से नियमित एनबीआर का भारत को नियर्ति इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है ।

ख. इस समय लागू पाटनरोधी सीमाशुल्क यदि हट दिया जाता है तो पारिंट आयातों से स्वदेशी उद्योग को आर्थिक हानि होगी ।

12. जापान मूल के या वहाँ से / नियर्ति एनबीआर के आयातों पर लागू किया जा रहा पाटनरोधी सीमाशुल्क जारी रखना उचित समझा जाता है । पाटनरोधी
शुल्क, २०० ७५४२/- धारी भोटी रुपन + लोडन /

13. उपरोक्त के अधीन रहते हुए, अधिसूचना तारीख 19 अक्टूबर, 1995
द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष अपरिवर्तित है ।

14. पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार, इस आदेश के विरुद्ध अपील कस्टम्स
एक्साइज एंड गोल्ड एक्स्ट्रैक्ट अपीलीय फ़िल्यूनल में की जा सकती है ।

रति विनय द्वा, पदनामित प्राधिकारी
एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 1999

Subject : Review of Anti-dumping duties concerning imports of NBR—final findings

No. 38/6/97/ADD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:
 - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) issued a public notice vide notification no. 38/4/97/ADD dated the 12th May, 1998, initiating review of definitive Anti Dumping Duty recommended on imports of NBR originating in or exported from Japan vide notification dated 19th Oct., 1995.
 - ii. The investigations concluded by the Authority vide notification dated 19th Oct., 1995 have been referred to as “the previous investigations”;
 - iii. The Authority issued a public notice dated 12th May, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of anti dumping duty concerning imports of NBR, classified under custom heading 4002.59 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Japan (also referred to as the subject countries hereinafter);
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations (whose details were made available by Gujarat Apar Polymers Ltd., the petitioner in the previous investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2);
 - v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumers of NBR in India (whose details were made available by Gujarat Apar Polymers Ltd. in the previous investigations) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
 - vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of NBR in India during the period of review.
 - vii. The Embassy of Japan in New Delhi was informed about the initiation of the review investigations in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent

- to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers. No exporter/producer, however, filed any response;
- viii. A questionnaire was sent to the known importers and/or consumers of NBR in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4);
- ix. A questionnaire was sent to Gujarat Apar Polymers Ltd. (also referred to as Gujarat Apar hereinafter) calling for necessary information in accordance with rule 6(4). Gujarat Apar filed its response;
- x. The Authority held a public hearing on 17th Nov., 1998 to hear the views orally. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals;
- xi. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by an interested party;
- xii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1997 to 31st March, 1998.
- xiii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

B. VIEWS OF GUJARAT APAR

2. Gujarat Apar made the following submissions:

- (a) Although the anti-dumping duty imposed on Japan and other countries have helped Gujarat Apar survive, the company has been constantly subjected to severe unfair competition. The present level of duties is not sufficient and the imports continue at dumped prices.
- (b) The exporters from Japan have not furnished any information with regard to dumping. The normal value of NBR in Japan can be determined on the basis of the prices published in Japan Chemical Week, which works out to an average of Yen 440 per kg. considering average exchange rate, the normal value works out to US \$ 3562 pmt.
- (c) The export price can not be determined on the basis of the information published by DGCI&S as the importers are clearing NBR through different H. S. Codes. The export price should be determined on the basis of the information compiled by various agencies, which indicates that 887 MT NBR was imported from Japan at an average CIF price of Rs. 61.28/kg.
- (d) The export price, when adjusted for expenses incurred on exports to India establishes that massive dumping of 200% plus continues.
- (e) The landed cost, including anti-dumping duty is not sufficient to fetch a reasonably profitable price. Accumulated losses continues and the company has not been able to pay any dividends since inception.

- (f) The exporters have bigger potential to cause injury in future, which is evident from imports before the imposition of duty.
- (g) The fair selling price of NBR in India should be such so as to enable the domestic industry to recover costs of R&D, technical services, cost of capital, etc. The capacity utilisation should be based on specific circumstances of the domestic industry rather than any hypothetical levels.
- (h) Variable anti-dumping duty should be fixed in Dollar terms.
- (i) Anti-dumping duty on imports from Korea be increased to an appropriate level.

C. **VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3 None of the exporters/producers have responded to the Authority and offered any comments. Some of the importers as also All India Rubber Industries Association furnished their views, which are as under:

- (a) The Authority recommended a lower duty of Rs. 19306 pmt as the injury margin was less than the dumping margin.
- (b) Based on FOB export price of US \$ 1058 pmt during 1993-94, the fair selling price of the domestic industry works out to Rs. 89483 pmt (for the investigation period) including anti-dumping duty but excluding CVD.
- (c) Article 11.2 of the Agreement on Anti Dumping provides that the review should examine whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were to be removed or varied or both. Material injury to Gujarat Apar has been eliminated after the imposition of anti-dumping duty and the same is borne out by the annual report of the company for 1996-97, wherein the Director's report mentions that Gujarat Apar is in a comfortable position due to the imposition of anti-dumping duty on NBR. This is borne out by the fact that the Gujarat Apar has made profit subsequent to imposition of anti-dumping duty. It is therefore necessary to examine whether the injury is likely to recur if the duty were removed or varied.
- (d) Imports of NBR during the investigation period were 857 MT at an average CIF price of US \$ 1695.
- (e) Based on weighted average CIF price, the landed value during the period of review works out to Rs. 111683 pmt, without including countervailing duty. The domestic price could have been higher than Rs. 111683 pmt plus 5%. Gujarat Apar could have therefore sold NBR at about Rs. 112000 pmt. The domestic price during April, 1997 was Rs. 91000 pmt and the ex-factory price works to Rs. 83500 pmt. This price is much below landed value of imports from Japan without charging anti-dumping duty. The removal of anti-dumping duty will still enable Gujarat Apar to realise a reasonable price for their NBR.
- (f) The customs duty on NBR has been reduced from 85% (1993-94) to 45% as on 31.3.1998. During the same period, the duty on Acrylonitrile has been reduced from 40% to 15%, resulting in constant reduction in the cost of NBR.
- (g) Material injury to Gujarat Apar cannot recur since the company is selling NBR much below the landed value in case the anti-dumping duty is removed. The reasons for inability of the

company to sell at a price equivalent to landed value of imports are not attributable to imports from Japan. It has been admitted by Gujarat Apar that it has been forced to sell at a competitive price in view of imports from Korea.

- (h) The share of imports of NBR from Japan has gone down from 66% in 1995-96 to 17.5% in 1997-98.
- (i) The CIF export price from all other countries is higher than the export price from Japan in view of the fact that common standard grades are imported from Japan as compared to special grades imported from other countries, in spite of which the landed cost of imports from Japan is higher than other countries (in view of anti-dumping duty in force).
- (j) The imports have further become expensive after introduction of special additional duty of 4% which works out to 6.844%. imports are therefore taking place under DEEC or only when the grades required are not substitutable with grades available from local sources.
- (k) The anti-dumping duty on imports from Japan should be removed in view of the following:
 - (i) Increase in import price,
 - (ii) Reduction in customs duties,
 - (iii) Increase in exchange rates,
 - (iv) Increase in landed value of imports,
 - (v) No injury to Gujarat Apar,
 - (vi) Reduction in production costs of Gujarat Apar.

In view of the foregoing, the anti-dumping duty on imports from Japan should be removed.

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

- 4. The submissions made by Gujarat Apar, importers, consumers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt hereinafter.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, DOMESTIC INDUSTRY AND LIKE ARTICLES

- 5. The final findings notified earlier with regard to the product under consideration, domestic industry and like articles remains unchanged.

F. DUMPING

- 6. None of the exporters or producers from Japan have responded to the Authority. None of the importers or consumers of NBR in India have furnished any information relevant to determination of dumping. Gujarat Apar has claimed that the dumping continues from Japan and has claimed that normal value of NBR in Japan can be determined on the basis of the prices published in Japan Chemical Week. Since none of the other interested parties have furnished any information, the Authority considers it appropriate to determine normal value of NBR in Japan based on the information published in Japan Chemical Week. Further, since none of the other interested parties have furnished any information with regard to price adjustments, the same have been allowed on the basis of

information furnished by Gujarat Apar and the basis considered in the previous investigations.

7. With regard to export price, the Authority notes that while Bombay Chemicals & Rubber Products have claimed an export price of US \$ 1695 pmt, Gujarat Apar has claimed export price of US \$ 1500 pmt. Further, Bombay Chemicals & Rubber Products have furnished necessary evidence in terms of relevant invoices. The Authority, therefore, considers it appropriate to determine the export price on the basis of the information furnished by Bombay Chemicals & Rubber Products.
8. The export price has been adjusted for expenses which the exporters should have incurred on exports to India on the basis of information furnished by Gujarat Apar and the information considered in the previous investigations in the absence of any direct information from the exporters from Japan.
9. The normal value and export price so arrived at are considered as ex-factory prices. Since none of the exporters from Japan have co-operated with the Authority, the Authority has not assessed separate dumping margins for different exporters. The dumping margin comes to 113.4%

G. INJURY AND CAUSAL LINK

10. The argument that the selling prices of Gujarat Apar are lower than the landed value of imports after charging the prevailing level of anti-dumping duty or even without charging the prevailing level of anti-dumping duty is not relevant to determine whether injury to the domestic industry would recur in case the anti-dumping duty in force is suspended. The only relevant factors to decide whether the duties in force should be continued or not are the dumping margin and the extent of injury without considering the prevailing anti-dumping duty. The actual selling prices of Gujarat Apar are a function of a number of other factors. The Authority has determined fair selling price and has found that the landed value of imports in the investigation period were lower than the fair selling price of the domestic industry in case the anti-dumping duty in force is not considered. Further, mere statement in the Director's report that the company is in a comfortable position due to imposition of anti-dumping duty on NBR does not imply that the duty in force should be suspended. In fact, if the position of the domestic industry has improved as a consequence of the imposition of anti-dumping duty, it merely reinstates the demand of the domestic industry that it should be provided due protection from unfairly traded dumped imports. Comfortable position in the past does not imply comfortable position in future, particularly when the comfortable position in the past could be due to the measures being reviewed. The decline in the market share of Japan also does not warrant suspension of duties. With regard to lower landed value of imports from Korea forcing the domestic industry to sell lower and request of the domestic industry to appropriately increase anti-dumping duty on imports from Korea, the Authority notes that the present investigations are only against Japan. The anti-dumping duty on imports from the Republic of Korea cannot be altered without following the due process of investigation even if the imports from these sources are causing injury to the domestic industry and the level of duties are inadequate.

H. FINAL FINDINGS

11. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:

- a. NBR originating in or exported from Japan has been exported to India below its normal value;
 - b. the domestic industry would suffer material injury from dumped imports in case the anti-dumping duty in force is removed.
12. It is considered appropriate to continue the anti-dumping duty in force on imports of NBR originating in or exported from Japan. The anti-dumping duty shall be Rs. 7882/- per MT.
13. Subject to above, the final findings notified vide notification dated 19th Oct., 1995 are unaltered.
14. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority
& Addl. Secy.

